भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3473

सोमवार, 10 अगस्त, 2026 / 19 श्रावण, 1948 (शक)

गैर-लकड़ी वनोपज (एनटीएफ़पी) में कार्यरत कामगार

†3473. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश के असंगठित क्षेत्र में गैर-लकड़ी वनोपज (एनटीएफ़पी) के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन में लगे श्रमिकों के संबंध में कोई आधिकारिक अनुमान है और यदि हाँ, तो विशेषकर झारखंड और ओडिशा के संदर्भ में तत्संबधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए गैर-लकड़ी वनोपज (एनटीएफ़पी) संग्राहकों की संख्या का, विशेषकर झारखंड और ओडिशा के संदर्भ में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-लकड़ी बनोपज (एनटीएफ़पी) संग्राहकों की आय, मजदूरी के स्तर, आजीविका की स्थिति और औपचारिक उद्योगों तथा मूल्य शृंखलाओं में उनके योगदान का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर-लकड़ी वनोपज (एनटीएफ़पी) संग्राहकों और अन्य वन-आधारित श्रमिकों के लिए कौशल विकास, कल्याणकारी उपायों और आजीविका सहायता की योजना बनाने हेतु ई-श्रम डेटा का उपयोग किया जा रहा है, और

(ङ) यदि हाँ, तो झारखंड और ओडिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वानिक श्रमिकों और संबंधित कामगारों सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। यह ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

ई-श्रम पोर्टल पर 31.85 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है। पूरे देश में "वानिकी श्रमिक और संबंधित कामगार" उपजीविका के अधीन पंजीकृत असंगठित कामगारों की कुल संख्या 3,95,102 है, जिसमें झारखंड और ओडिशा राज्य के क्रमशः 13,581 और 59,018 कामगार शामिल हैं।

जारी...2/-

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को एक वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम -"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, ताकि ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ और पहुंच प्रदान की जा सके, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी - जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई - जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत तथा झारखंड और ओडिशा में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन नामांकित वानिकी श्रमिकों और संबंधित कामगारों का ब्यौरा संलग्नक में है।

*

संलग्नक

"गैर-लकड़ी वनोपज (एनटीएफ़पी) में कार्यरत कामगार" के संबंध में श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3473 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत तथा झारखंड और ओडिशा में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन नामांकित वानिकी श्रमिकों और संबंधित कामगारों का ब्यौरा।

योजनाएं	झारखंड में नामांकन	ओडिशा में नामांकन
वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	11,805	53,660
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)	23	127
विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबी - जी आरएएम जी)	3,422	15,145
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	1,276	5,367
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	16	156
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	67	895
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई - यू)	32	269
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	5	1
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	1,455	6,771
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	5,430	23,361
आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	7,317	66
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	1,595	7,629
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	79	2

****